

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



सत्यमेव जयते

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2001 कार्तिक 7, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-385/2001/वा.क./पांच (60)—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देशित करती है कि इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यवसायी, जिसके व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ़ में हो, के द्वारा इमारती लकड़ी (अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान क्रय की गई) का विक्रय छत्तीसगढ़ में स्थित उसके व्यवसाय स्थल से अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान करने पर, उसके द्वारा किये गये ऐसे विक्रय के र्छ ओवर पर देय कर की गणना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से दिनांक 31-03-2002 तक की अवधि के दौरान 1 प्रतिशत की दर से की जावेगी.

Raipur, the 29th October 2001

NOTIFICATION

No. F-10-385/2001/CT/V(60)—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby directs that the tax payable under sub-section (1) of Section 8 of the said Act, by any dealer having his place of business in the State of Chhattisgarh in respect of sales of Timber (purchased in the course of interstate trade or commerce), by him from any such place of business in the course of interstate trade or commerce, shall, with effect from the date of publication in the Official Gazette, till 31-3-2002, be calculated at the rate of one percent on his turnover of such sales.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



सत्यमेव जयते

पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2001 — पौष 10, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 29-12-2001 को छ.ग. के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई.एस उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 6) अधिनियम, 2001

वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2001 (क्रमांक 23 सन् 2001) है.
2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक सौ उनसठ करोड़, पचासी लाख, सतहत्तर हजार, तीन सौ उन्नास रूपया हाता ह उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.
3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

संक्षिप्त नाम.

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये
राज्य की संचित निधि में से
159,85,77,319 रुपयों का दिया
जाना.

विनियोग.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्याक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनाधिक राशियां		योग
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	
(1)	(2)	(3)		
		रुपये	रुपये	रुपये
01 सामान्य प्रशासन	राजस्व	2,79,96,531	24,00,000	3,03,96,531
02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	34,65,000	0	34,65,000
03 पुलिस	राजस्व	10,00,600	0	10,00,600
04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	50,000	0	50,000
07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,49,00,000	0	1,49,00,000
	पूंजी	14,53,500	0	14,53,500
10 वन राजस्व	राजस्व	16,00,000	0	16,00,000
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	30,52,000	0	30,52,000
13 कृषि	राजस्व	13,29,30,000	0	13,29,30,000
14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,51,54,000	0	5,51,54,000
18 श्रम	राजस्व	38,94,000	0	38,94,000
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
24 लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	राजस्व	30,00,00,000	0	30,00,00,000
25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	33,89,000	0	33,89,000
26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	30,00,000	0	30,00,000
27 स्कूल शिक्षा	राजस्व	4,47,25,000	0	4,47,25,000
28 राज्य विधान मंडल	राजस्व	38,00,000	0	38,00,000
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	2,00,83,200	17,00,000	2,17,83,200
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय	राजस्व	19,05,28,000	0	19,05,28,000
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,09,000	0	12,09,000
32 जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	22,50,000	0	22,50,000
36 परिवहन	राजस्व	84,35,000	0	84,35,000
37 पर्यटन	राजस्व	1,80,000	0	1,80,000
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,13,66,000	0	2,13,66,000

(1)	(2)	(3)		
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	19,74,29,000	0
		पूँजी	6,58,46,000	0
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	पूँजी	4,00,00,100	0
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	22,04,000	0
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूँजी	2,71,62,000	0
48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	राजस्व	8,50,000	0
55	महिला एवं बाल विकास कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	3,00,000	0
56	गामोद्योग	राजस्व	8,00,000	0
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूँजी	20,00,000	0
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	राजस्व	6,33,72,000	0
65	विमानन विभाग	पूँजी	86,61,288	0
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	6,00,000	0
67	लोक निर्माण कार्य भवन	राजस्व	4,24,000	0
		पूँजी	100	0
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	87,50,000	0
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	6,64,00,000	0
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	26,36,00,000	0
82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	6,18,000	0
योग		राजस्व	1,44,93,54,331	41,00,000
		पूँजी	14,51,22,988	0
वृहद योग			1,59,44,77,319	41,00,000
				1,59,85,77,319